.उच्च न्यायालय में मामला और यदि न्यायाधिकरण ने अस्वीकार कर दिया, तो मामले को *संदर्भित* करने के लिए न्यायाधिकरण को एक परमादेश जारी करना, क्योंकि किसी भी स्थिति में, जवाब एक क्षमा, निष्कर्ष होगा।ऐसी स्थिति में, यह माना जाना चाहिए कि मामला उच्च न्यायालय को बताया गया था और पहले के फैसले के बाद उच्च न्यायालय ने इन तर्ज पर प्रश्न का उत्तर दिया था/'

इसी प्रभाव के लिए सी. आई. टी. बनाम *में* निर्णय *हैं/इंडियन प्रेस, एक्सचेंज* (2) और *सी.* आई. *टी. बनामकेरल S.R.T.C.* ट्रस्ट (3)।

(5) सी. आई. टी. बनाम *में उच्चतम न्यायालय/चंदर भान हर्भजन लाल* (4) ने अभिनिर्धारित किया कि जहां उठाए गए कानून का प्रश्न सारवान नहीं है और प्रश्न का उत्तर स्वयं स्पष्ट है, न्यायालय न्यायाधिकरण से प्रश्न को संदर्भित करने की अपेक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है।तत्काल मामले में, मैसर्स सोवरिन निट वर्क्स मामले (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के फैसले को देखते हुए संदर्भित किए जाने वाले प्रश्न का उत्तर स्वयं *स्पष्ट है/*

(6) कोई योग्यता नहीं है।बर्खास्त कर दिया।

जे एस टी/

माननीय एस. एस. ग्रेवाल और एम. एल. कौल, न्यायमूर्ति के समक्ष

प्रदीप *कुमार-याचिकाकर्ता/*

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता।

1994 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3287

23नवंबर, 1994

भारत का *संविधान/1950-कलाएँ/226/227-पुलिस बल को आर. ई. सी. एम.-याचिकाकर्ता शारीरिक मानक को पूरा नहीं कर रहा है शारीरिक मानक में छूट का दावा करना-छूट की कोई शक्ति नहीं/*

अभिनिर्धारित किया कि भर्ती के नियमों के अनुसार, बोर्ड किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के पक्ष में इन मानकों में ढील नहीं दे सकता है।साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं, हालांकि वे विज्ञापन सूचना में निर्धारित आवश्यक शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे।याचिकाकर्ता को एक बहुत ही अनुशासित विनियमित बल में नियुक्त किया जाना था और चूंकि सहायक उप निरीक्षकों के पद

अत्यधिक संवेदनशील पद हैं और वे राज्य की सुरक्षा के लिए भी कार्यरत हैं, इसलिए शारीरिक परीक्षण का अत्यधिक महत्व है और भर्ती प्राधिकरण द्वारा ऐसे मानकों में किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं दी जा सकती है।चूंकि याचिकाकर्ता ने आवश्यक भौतिक मानकों को पूरा नहीं किया, जो चयन प्रक्रिया का एक बहुत ही आवश्यक घटक था, इसलिए याचिकाकर्ता के पास यह दावा करने *का कोई* अधिस्थिति नहीं था कि उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता संजीव शर्मा ने कहा,*

प्रतिवादी की ओर से पी. एस. कादियान, डी. ए. जी., *हरियाणा, पी. एस. पटवालिया, अधिवक्ता*

आदेश

एम. एल. *कौल, जे.*

(1) डेली ट्रिब्यून में 7 दिसंबर के अपने अंक में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 6/92 के जवाब में।1992 प्रतिवादी द्वारा पुलिस के सहायक उप-निरीक्षकों की 102 रिक्तियों को भरने के लिए, जैसा कि संलग्नक पी/एल के रूप में निहित है, याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने उक्त विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया।याचिकाकर्ता द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पूर्वाहन बाद, उन्हें 30 अक्टूबर, 1993 को सुबह 9 बजे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मधुबन (कर्नाड) में शारीरिक परीक्षण पूर्वाहन लिए बुलाया गया और उस तारीख को अन्य 76 उम्मीदवारों पूर्वाहन साथ उनका शारीरिक परीक्षण आयोजित किया गया।प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों ने योग्यता कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती को मापा और केवल उन उम्मीदवारों को योग्यता कार्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा गया जो न्यूनतम निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करते थे।याचिकाकर्ता की ऊँचाई और छाती को भी मापा गया, और वे निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जैसा कि उपरोक्त संलग्नक पी-1 में निहित है।इसके बाद, माप का संचालन करने वाले अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसकी ऊँचाई कम बी. वी. 1 से. मी. थी, हालांकि पहली बार जब उसकी ऊँचाई मापी गई, तो यह पाया गया कि वह विज्ञापन नोटिस में निर्धारित आवश्यक शारीरिक मानकों का पालन कर रहा था।ऊँचाई और छाती को मापने के बाद, याचिकाकर्ता को योग्यता प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा गया और वह अन्य 76 शारीरिक प्रतियोगिताओं में सभी चार प्रतियोगिताओं में शीर्ष पर रहा।

जिन उम्मीदवारों की उस तारीख को जांच की गई थी।चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई के बारे में संदेह पैदा किया था, इसलिए उन्होंने खुद को फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मापा और उनकी ऊंचाई 5 '-7'

पाई गई।इसके बाद याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था और इसलिए, वह प्रतिवादी द्वारा जारी की गई चयन सूची को रद्द करने *के* लिए सरशियोरेराई की एक रिट जारी करके इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है और *प्रतिवादी* को सहायक उप निरीक्षक के पद के खिलाफ याचिकाकर्ता को नियुक्त करने परमादेश देता है।

(2) प्रस्ताव की सूचना जारी होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2, यानी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा आपत्तियां दायर की गईं और याचिकाकर्ता के कथनों को इस आधार पर विरोधाभासी बनाया गया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है ताकि इस न्यायालय को मामले में रोविंग जांच करने के लिए राजी किया जा सके।याचिकाकर्ता सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करता था और अधिसूचना के अनुसार चयन के लिए निर्धारित शारीरिक मानक निम्नानुसार थेः—

ऊँचाईः
5'—7"
छातीः
33" 1 "के विस्तार के साथ।
(अर्थात 33 "X 34 ½ ")

सहायक उप निरीक्षक का पद, जिसके लिए विज्ञापन सूचना के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल थी।

(2) ए. एच. वे उम्मीदवार, जिन्होंने शारीरिक माप को पूरा किया और (लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा) उत्तीर्ण की, उन्हें *वाइवा* वॉस टेस्ट के लिए बुलाया गया।उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था और तदनुसार सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए चयन के अनुसार जारी की गई थी।

(3) याचिका भी दायर की गई थी और याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं को याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रतिकृति में दोहराया गया था।

(4) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और फाइल पर रिकॉर्ड पर विचारपूर्वक विचार किया है।यह पक्षों का स्वीकृत मामला है कि सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा सहायक पुलिस उपनिरीक्षकों के 102 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और याचिकाकर्ता ने विज्ञापन संख्या 6/92 के अनुपालन में एक पद के लिए आवेदन किया और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।संक्षेप में, अधिसूचना में कहा गया है कि सहायक उप निरीक्षकों के उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, जिसमें 100 अंकों के दो पेपर शामिल थे, जो इस प्रकार हैः—

(i) बी. ए. मानक की सामान्य अंग्रेजी और हिंदी; और

(ii) सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन।

सभी उम्मीदवारों (आरक्षित श्रेणियों सहित) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम योग्यता अंक प्रत्येक पेपर में 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत थे।वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते थे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था।शारीरिक परीक्षण में, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित चार परीक्षणों में से तीन परीक्षणों में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता थीः—

1. 100 मीटर की दौड़ 14.5 सेकंड में;
2. 800 मीटर ढाई मिनट में दौड़ते हैं।
3. लंबी कूद-15 फीट; और
4. ऊँची कूद-4 फुट।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 11 "(33" x 34i ") हाई चेस्ट के विस्तार के साथ 5 '-7" ऊंचाई और 33 "होने के साथ शारीरिक मानकों को भी साबित करना था।

(7) हाथ में मामले में, याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया

30 अक्टूबर, 1993 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मधु में परीक्षा, जिसके लिए[63] कैंडिडा * उपस्थित हुए, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरे।इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह कथन कि ऊंचाई और छाती में जेपरफ़ेक्ट पाए जाने के बाद उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरने के लिए कहा गया था, इस तथ्य के लिए गलत है कि (याचिका के पैरा 4 में याचिकाकर्ता ने स्वयं इस दावे का यह कहकर खंडन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई के बारे में संदेह पैदा किया था और इसलिए, उसने खुद को फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मापा और उसकी ऊंचाई 5 '7 पाई गई।याचिकाकर्ता का यह दावा अपने आप में इस तथ्य का संकेत है कि दौड़ने और कूदने में शारीरिक माप और शारीरिक परीक्षण दोनों एक साथ आयोजित किए गए थे और दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने दौड़ और कूद के संबंध में परीक्षणों में अर्हता प्राप्त की हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेकिन वह अपनी ऊंचाई और छाती के संबंध में शारीरिक मानकों को बनाए रखने में विफल रहा।

(8)पुलिस उप महानिरीक्षक की उपस्थिति में बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता को शारीरिक रूप से मापा गया था।मापने पर, याचिकाकर्ता को जे "ऊंचाई में और एलजे" x1। "छाती में छोटा पाया गया और इसलिए, तार्किक और कानूनी रूप से वह साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं था, क्योंकि उसने विज्ञापन सूचना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था कि उसे एलजे" (33 "x 34 ½ ") के विस्तार के साथ 5 '-7 "और छाती 33" की ऊंचाई रखनी चाहिए।एक बार जब याचिकाकर्ता विज्ञापन नोटिस में निर्धारित शारीरिक

मानकों को बनाए रखने के लिए सही मुकाम पर नहीं आया, तो वह कानून के तहत साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं था।

(9) भर्ती के नियमों के अनुसार, बोर्ड किसी भी तरह से इन मानकों में छूट नहीं दे सकता था ताकि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सक्षम किया जा सके, हालांकि वह विज्ञापन नोटिस में निर्धारित आवश्यक शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर रहा था। याचिकाकर्ता को एक बहुत ही अनुशासित और विनियमित बल में नियुक्त किया जाना था और चूंकि सहायक उप निरीक्षकों के पद अत्यधिक संवेदनशील पद हैं / और वे राज्य की सुरक्षा के लिए भी नियोजित हैं, इसलिए शारीरिक परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और भर्ती प्राधिकरण द्वारा ऐसे मानकों में किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं दी जा सकती है। चूंकि याचिकाकर्ता ने आवश्यक शारीरिक मानकों को पूरा नहीं किया, जो चयन प्रक्रिया का एक बहुत ही आवश्यक घटक था, इसलिए, याचिकाकर्ता के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं था कि उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था और यह पाया गया कि उसे पद के लिए ठीक ही खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वह आवश्यकता और विज्ञापन संख्या 6/92 में निर्धारित शर्तों के अनुसार चिन्हित नहीं हुआ था।

(10) याचिकाकर्ता स्वयं, जिस दिन से बोर्ड द्वारा उसकी शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उस दिन से ही आशंकित था कि वह चिन्हित नहीं हुआ था, क्योंकि यह पाया गया था कि वह ऊंचाई में ½'' इंच और छाती में 1/2x 1/2 इंच छोटा था और इसलिए, उसके अनुसार, उसने खुद को फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मापा, और उसकी ऊंचाई 5'—7" पाई गई। वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शारीरिक परीक्षा में फेल हो गया, जब उसकी परीक्षा बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ की उपस्थिति में आयोजित की गई, जो पुलिस उप महानिरीक्षक था और जो यह कहने के लिए बेहतर स्थिति में था कि याचिकाकर्ता के पास सहायक उप निरीक्षक के रूप में चयन के लिए आवश्यक शारीरिक मानक हैं, जैसा कि भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता को सहायक उप निरीक्षक के रूप में चयन के लिए खारिज करने में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई अवैधता या अनुचितता नहीं की गई है, इस तथ्य के लिए कि उसने आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी और इस प्रकार, उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। इसलिए, वह सही तरीके से नहीं चुना जा सका। यह, याचिकाकर्ता, इसलिए, निराधार होने के कारण खारिज किया जाता है। फाइल को अभिलेखों में शामिल किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा